



अग्रभारत

www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19

अंक: 109

आगरा, बुधवार 06 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

जयशंकर और अमेरिकी कमांडर पापारो की रणनीति से चीन की बड़ी बेचैनी

नौसैनिक तालमेल, तकनीक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अहम मुद्दे पर हुई बात

नई दिल्ली, (ए)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। छह दिवसीय भारत दौर पर आए एडमिरल पापारो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ हुई इस बातचीत का मुख्य केंद्र हिंद महासागर में नौसैनिक तालमेल, उभरती सैन्य तकनीक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रणनीतिक संतुलन साधने जैसे अहम मुद्दे रहे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिससे चीन में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है।



एडमिरल सैमुअल जे पापारो की यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत

पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान एडमिरल पापारो भारतीय अधिकारियों के साथ दोनों देशों की

साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर बातचीत करेंगे। इनमें नई तकनीक का इस्तेमाल, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना, रक्षा क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और तेजी से बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा से निपटने जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और भारत ऐसी रक्षा साझेदारी तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, और यह एडमिरल पापारो की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत प्रमुख रक्षा साझेदारी को दर्शाती है। यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही उपस्थिति और उसके रणनीतिक हितों को भी दोहराती है।

यह केवल एडमिरल पापारो की

मुलाकात नहीं थी, बल्कि सितंबर के अंत में भी इसी तरह की उच्च-स्तरीय बातचीत हुई थी। 28 सितंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और अमेरिकी सेना की प्रशांत कमान के डिटी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी. वोवेल ने नई दिल्ली में मुलाकात की थी। भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने बताया कि इस बैठक में संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यासों के जरिए दोनों सेनाओं की साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर भी बात हुई थी। युद्ध अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यासों की सफलता ने संयुक्त अभियानों में दोनों सेनाओं के बेहतर तालमेल को साबित किया है और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

2200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, देश के सात राज्यों से होकर गुजरेगा

नई दिल्ली, (ए)। सरकार ऐसे कॉरिडोर पर काम कर रही है, जो 2,200 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली से चलकर चेन्नई तक ले जाता है। इस दौरान एक्सप्रेसवे पूरे सात राज्यों से गुजरेगा। यह रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे से शुरू होकर बुंदेलखंड ई-वे के रास्ते हैदराबाद-चेन्नई एक्सप्रेसवे के जरिये पूरा होगा। इसमें दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिये भी चेन्नई तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि, यह रास्ता करीब 250 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। इससे सफर का समय भी बढ़ जाएगा, लेकिन बुंदेलखंड के जरिये इस दूरी को तय करने में समय भी कम लगेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। दिल्ली से चेन्नई तक जाने के लिए जिन तीन एक्सप्रेसवे से गुजरना होगा, उसमें सबसे पहला है यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली और नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की दूरी 165 किलोमीटर है और यह जेवर, अलीगढ़, मथुरा के रास्ते आगरा पहुंचता है। इसके बाद आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के जरिये धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है। ग्वालियर के आगे बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे आपका सफर पूरा होगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह एक्सप्रेसवे नागपुर के लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और महाराष्ट्र



के नागपुर तक जाता है। इस रास्ते झांसी, बबीना, सागर, लखनादौन और सिवनी से होकर गुजरा जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-44 की चार और 6 लेन की सड़क भी जुड़ती है। यह राजमार्ग दो राज्यों को जोड़ने वाले नेटवर्क का काम करता है। इसके बाद शुरू होती है महाराष्ट्र से तेलंगाना की यात्रा। इसके लिए नागपुर से हैदराबाद तक का सफर पूरा होता है। यह सफर नागपुर, हैदराबाद, बैंगलुरु एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से पूरा होता है। यह रास्ता नागपुर से आदिलाबाद और निजामाबाद से होते हुए तेलंगाना के हैदराबाद तक जाता है।

तेलंगाना से तमिलनाडु तक जाने के लिए हैदराबाद-अमरावती-चेन्नई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पकड़ना होगा।

यह रूट हैदराबाद से नलगोंडा, गुंटूर, अमरावती, अंगे और नेल्लोर के जरिये जाता है। यह रास्ता आखिर में नेशनल हाईवे-16 से जुड़ता है और सीधे चेन्नई तक जाता है। दिल्ली से चेन्नई तक जाने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता है, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जाता है। यह एक्सप्रेसवे आगे चलकर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और वहां से चेन्नई जाने के लिए पुणे-बैंगलुरु नेशनल हाईवे यानी एनएच-48 का रास्ता पकड़ना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस रूट से चेन्नई जाते हैं तो पहले दिल्ली-मुंबई ई-वे पकड़ना होगा, फिर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और बैंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे से आपका सफर पूरा हो जाएगा।

भारतीय लोग पाकिस्तानियों से जीते हैं ज्यादा, बांग्लादेश, अमेरिकियों से है कम

नई दिल्ली, (ए)। भारतीयों की औसत उम्र पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा के लोगों की तुलना में कम। 2023 में भारत में जन्म के समय औसत उम्र 71 साल थी, जबकि पाकिस्तान में यह 68.2 साल, बांग्लादेश में 72.7 साल, अमेरिका में 78.5 साल और कनाडा में 81.4 साल थी, लेकिन ज्यादा समय तक जीने का मतलब हमेशा अच्छी सेहत के साथ ज्यादा साल जीना नहीं होता है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में स्वस्थ जीवन की औसत अवधि 60.6 साल थी, जबकि



2019 में यह 60.5 साल थी। 2021 में यह घटकर 58.4 साल हो गई थी और फिर 2022 में सुधरकर 60.2 साल हो गई। ये आंकड़े डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स का हिस्सा हैं, जिन्हें हाल ही जारी किया गया है। इनमें 2000 से 2023 तक औसत उम्र, स्वस्थ जीवन की औसत अवधि, मौत के कारण और बीमारी के बोझ

जैसी जानकारी शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वैश्विक औसत उम्र महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है, जबकि स्वस्थ जीवन की औसत अवधि में सुधार धीमी गति से हुआ है। यह अंतर ज्यादा उम्र के भारतीयों में ही दिखता है। 2019 में 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति के लिए आगे 18.4 साल जीने की उम्मीद थी, जबकि 2023 में यह उम्मीद 18.8 साल हो गई। लेकिन इनमें से 13.7 साल पूरी तरह स्वस्थ रहकर बिताने की उम्मीद थी, जो 2019 में 13.4 साल थी। भारत में बीमारियों का स्वरूप तेजी से बदला है। संक्रामक बीमारियां, जैसे टीबी और दस्त का संक्रमण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं।

हर सड़क के साथ फुटपाथ जरूरी, पायलट प्रोजेक्ट के लिए पांच शहर चुनें

नई दिल्ली, (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश के पांच शहरों की पहचान कर वहां फुटपाथ से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सड़क के साथ पैदल चलने वालों के लिए उचित रूप से चिह्नित और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ उपलब्ध कराना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए फुटपाथ की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को पीठ ने केंद्र सरकार से ऐसी केंद्रीय अर्थोद्दी की पहचान करने को कहा, जो देशभर में फुटपाथों के निर्माण, उपलब्धता और रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। अदालत ने जोर दिया कि केवल फुटपाथ बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखना और नियमित रूप से उनकी देखरेख करना भी आवश्यक है।

अर्थोद्दी के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पीठ ने पृष्ठ कि फुटपाथों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्रीय अर्थोद्दी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अदालत ने कहा कि संबंधित अर्थोद्दी के पास पर्याप्त जमीन, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ताकि वह देशभर में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। पीठ ने केंद्र से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन पांच शहरों का चयन किया जा सकता है। केएम नटराज ने अदालत को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने की बात कही। इसके बाद पीठ ने केंद्र को जिम्मेदार अर्थोद्दी की पहचान करने और प्रस्तावित शहरों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 जून को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि निर्धारित और चिह्नित फुटपाथ पर पैदल चलना संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत के इस रुख का उद्देश्य पैदल यात्रियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को अक्सर सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अदालत ने फुटपाथों की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और उपयोगिता पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई।

निर्माण के साथ रखरखाव पर भी जोर

अदालत ने संकेत दिया कि देशभर में फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए एक प्रभावी और जवाबदेह तंत्र विकसित करना होगा। इसके तहत फुटपाथों का निर्माण, उनकी नियमित निगरानी, अतिक्रमण हटाने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। पांच शहरों में प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट के जरिए फुटपाथों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जा सकती है। इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय अर्थोद्दी और आवश्यक संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में जानकारी देनी होगी।

महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर दिग्गजों ने किया नमन

लखनऊ (ए)। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने किसान हितों, अधिकारों और सम्मान के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अन्यायताओं के अधिकारों और हितों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनके नेतृत्व और विचारों ने देश के किसानों की आवाज को मजबूती दी। उन्होंने उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों और वंचित वर्गों के हितों एवं अधिकारों के लिए समर्पित महान किसान नेता बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने भी किसान हितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए टिकैत के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया।उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि टिकैत ने किसानों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। किसानों को संगठित करने और उनके हित, अधिकार एवं सम्मान के लिए किए गए उनके प्रयासों को उन्होंने स्मरणीय बताया। सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के अधिकार और सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने ग्रामीण समाज के उत्थान और किसानों के प्रति टिकैत के समर्पण को भी याद किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने टिकैत को किसानों, पिछड़ों और शोषितों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित नेता बताते हुए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न नेताओं के संदेशों में महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलनों और किसानों के अधिकारों के लिए उनके लंबे संघर्ष को याद किया गया।

बंगाल उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर हिरासत में

नई दिल्ली, (ए)। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने उनके पार्टी कार्यालय से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लेने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। वहीं, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को जबरन उठया जा रहा है। मतदान के बीच इन घटनाओं से बंगाल की चुनावी गतिविधियां चर्चा में आ गई हैं।

जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटें, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटें, पुडुचेरी की शृङ्गनचावडी विधानसभा सीट और असम की नागंव लोकसभा सीट शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से मतदाता अपने मतार्थिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे तक नंदीग्राम में 20.89 प्रतिशत और रेजीनगर में 18.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सभी सीटों के चुनाव परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।



पोलिंग एजेंटों को उठाने का आरोप

नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिली हुई है। उनके मुताबिक, उनके एक पोलिंग एजेंट को भी उठा लिया गया है। मिलन प्रधान ने कहा कि उपचुनाव में मतदान करना नागरिकों का अधिकार है और लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने मतार्थिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की जानकारी चुनाव कार्यालय को दी गई, लेकिन वहां से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के

दौरान ऐसी घटनाओं को अनुचित बताया।

पार्टी कार्यालय से हिरासत में लिए गए हुमायूं कबीर

रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के बीच पुलिस हुमायूं कबीर को उनके पार्टी कार्यालय से अपने साथ ले गई। वह आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख होने के साथ विधायक भी हैं। इससे पहले मंगलवार सुबह उन्होंने रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया था। उनके बेटे गुलाम नबी आजाद भी रेजीनगर सीट से उम्मीदवार हैं। हुमायूं कबीर को हिरासत में लेने की कार्रवाई किस वजह से की गई, इस संबंध में पुलिस की ओर से तत्काल कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई। मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।

आसमान की नई ऊंचाइयों की ओर गुजरात: देश का प्रमुख फ्लाइटिंग ट्रेनिंग हब बनने की राह पर

अहमदाबाद (ए)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने आकाश में ऊँची उड़ान भरी है और गुजरात में सिविल एविएशन का मजबूत ढाँचा तैयार होने से कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के लिए गुजरात नेशनल हब बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और युवाओं के लिए कॉरियर के नए द्वार खुले हैं। गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) का मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करके एविएशन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए अग्रिम एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। सिविल एविएशन विभाग तथा गुजरात स्टेट एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (गुजसेल) के माध्यम से गुजरात ने अपना मजबूत एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में सिविल एविएशन विभाग द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन का विकास किया जा रहा है। इस ढाँचे के अंतर्गत राज्य के स्वाभिम्व वाले एयरपोर्ट तथा एयरट्रिप्स पर लगभग 1,500 वर्ग मीटर भूमि पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया द्वारा पात्र ऑपरेटर्स को आवंटित की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल एविएशन को मानवबल तैयार करना और निजी निवेश आकर्षित करना है।

भारत का सिविल एविएशन क्षेत्र बढ़ते यात्री ट्रैफिक, उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार और घरेलू एयरलाइनों द्वारा बढ़े पैमाने पर नए विमानों की खरीद के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। भारतीय एयरलाइनों ने संयुक्त रूप से लगभग 1,700 नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में अनुमानित 25,000 से 30,000 कॉमर्शियल पायलटों की मांग पैदा होने की संभावना है। इस उम्रते अवसर को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने सिविल



एविएशन विभाग तथा गुजरात स्टेट एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (गुजसेल) के माध्यम से विश्वस्तरीय पायलट प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

गुजरात बना भारत का फ्लाइटिंग ट्रेनिंग हब

हाल में राज्य में पाँच फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) कार्यरत हैं। इनमें से चार राज्य के स्वाभिम्व वाली मेहसाणा एवं अमरेली एयरस्ट्रिप्स पर कार्यरत हैं, जबकि एक एफटीओ भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा आवंटित जमीन पर भावनगर एयरपोर्ट में कार्यरत है। कार्यरत एफटीओ में मेहसाणा में स्कायनेक्स एयरो प्रा. लि. और ब्लू रे एविएशन प्रा. लि.; अमरेली में विजन फ्लाइटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गुजरात फ्लाइटिंग क्लब तथा भावनगर में ड्यूनेस एविएशन प्रा. लि. शामिल हैं। राज्य की एविएशन क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं को और गति मिलने वाली है, क्योंकि पाँच और फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन शीघ्र ही कार्यरत होंगे। इन सभी संस्थानों के कार्यरत होने के बाद गुजरात में कुल 10 फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन का नेटवर्क होगा, जो गुजरात को भारत के सबसे बड़े राज्य स्तरीय पायलट प्रशिक्षण इकोसिस्टम में से एक बनाएगा।

गुजरात के फ्लाइटिंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशनों ने संयुक्त रूप से अब तक 5,200 से अधिक एविएशन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है, 3,200 से अधिक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल)

धारक पायलट तैयार किए हैं और एफटीओ 200 से अधिक भावी पायलटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इन संस्थानों में गुजरात फ्लाइटिंग क्लब का विशेष स्थान है। वर्ष 1958 में वडोदरा एयरपोर्ट पर स्थापित यह संस्थान आज भी भारत का सबसे लंबे समय से कार्यरत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) मान्य फ्लाइटिंग ट्रेनिंग संस्थानों में से एक है।

अनुकूल मौसम गुजरात को अतिरिक्त लाभ देता है

एविएशन प्रशिक्षण क्षेत्र में गुजरात को अनेक कारक प्रतिसपर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। राज्य में पूरे वर्ष उड़ान के लिए अनुकूल मौसम उपलब्ध रहता है, एयरपोर्ट और एयरस्ट्रिप्स का व्यापक नेटवर्क है। इसके अलावा, राज्य के पास स्वयं के स्वाभिम्व वाला एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है।

साथ ही, मजबूत औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर, उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी तथा निवेशकों के अनुकूल नीति उपलब्ध है।

* मजबूत एफटीओ इकोसिस्टम से आर्थिक लाभ में वृद्धि विस्तृत हो रहा एफटीओ इकोसिस्टम पायलट तैयार करने के अलावा उल्लेखनीय आर्थिक लाभों का सृजन भी करेगा। प्रत्येक फ्लाइटिंग ऑर्गनाइजेशन के लिए विमानों, सिमुलेटर्स, मेंटेंनेंस हैंगर, फ्यूल इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, हॉस्टल और प्रशासनिक सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक होता है।

ऐसे निवेशों से गुजरात की एविएशन इकोनॉमी अधिक मजबूत होने के साथ कॉमर्शियल फ्लाइटिंग इंस्ट्रक्टर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेंनेंस इंजीनियर्स, फ्लाइट डिसेंसर्स, ऑपरेशन्स ऑफिसर्स, सेप्टी प्रोफेशनल्स, प्रशासनिक कर्मचारियों और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।